निवेशक खातों की संख्या 26 करोड़ पार

मुफ्त इलाज, पेंशन और सहायक उपकरण

सीनियर सिटीज़न्स के लिए केंद्र की सुविधा

मुंबई, 07 जून. देश के प्रमुख शेयर बाजार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) ऑफ इंडिया ने जून में 26 करोड़ निवेशक खातों की उपलब्धि हासिल कर ली.

एनएसई ने रविवार को एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि एक्सचेंज पर यूनीक ट्रेडिंग खातों की संख्या 26 करोड़ के आंकड़े को पार कर गयी है. खास बात यह है कि 25 करोड़ से 26 करोड़ का सफर चार महीने से भी कम समय में तय हुआ है जो निवेशकों की भागीदारी में निरंतर वृद्धि दिखाता है. पिछले एक साल में ही 4.3 करोड़ से अधिक निवेशक खाते एक्सचेंज से जुड़ चुके हैं. यह कुल खातों का लगभग 17 प्रतिशत है.

वहीं, 31 मई तक एनएसई में पंजीकृत यूनीक निवेशकों की संख्या 13.1 करोड़ से अधिक थी. ट्रेडिंग खातों की संख्या यूनीक निवेशकों से अधिक है क्योंकि एक निवेशक विभिन्न ब्रोकरों के माध्यम से कई ट्रेडिंग खाते रख सकता है. अप्रैल 2026 में यूनीक निवेशकों की संख्या 13 करोड़ के पार पहुंची थी.

> निवेशक खातों के मामले में 4.4 करोड़ के साथ महाराष्ट्र पहले स्थान पर है. यह कुल खातों का लगभग 17 प्रतिशत है. इसके बाद लगभग तीन करोड़ (11 प्रतिशत) खातों के साथ उत्तर प्रदेश, 2.2 करोड़ (8.6 प्रतिशत) खातों के साथ गुजरात, 1.5 करोड़ (5.9 प्रतिशत) खातों के साथ पश्चिम बंगाल और 1.5 करोड़ (5.8 प्रतिशत) खातों के साथ राजस्थान का स्थान है. ये पांच राज्य मिलकर देश के लगभग 49 प्रतिशत निवेशक खातों का प्रतिनिधित्व करते हैं. इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में निवेशक खातों की वृद्धि उल्लेखनीय रही है.

पीएफ पर मिलेगा 8.25% ब्याज, जल्द खाते में आएगा पैसा

नई दिल्ली, 07 जून. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएफ पर 8.25% ब्याज दर को पहले ही मंजूरी दे दी है, जो पिछले कुछ वर्षों में सबसे अधिक मानी जा रही है. अब करोड़ों नौकरीपेशा लोगों को इंतजार है कि यह ब्याज राशि उनके खातों में कब तक आएगी. सूत्रों के अनुसार, ब्याज की प्रोसेसिंग का काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है और वित्त मंत्रालय की अंतिम मंजूरी के बाद अगले कुछ हफ्तों में यह राशि चरणबद्ध तरीके से खातों में जमा होना शुरू हो सकती है. ईपीएफओ का कहना है कि ब्याज क्रेडिट करने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल है, इसलिए अलग-अलग क्षेत्रों और खातों में राशि आने का समय अलग-अलग हो सकता है.

जीडीपी वृद्धि 6.6% से अधिक हो सकती है

आर्थिक अनुसंधान प्रभाग एसबीआई रिसर्च की 'इकोरैप' की रिपोर्ट

नयी दिल्ली, 07 जून. भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान प्रभाग एसबीआई रिसर्च की शनिवार को जारी 'इकोरैप' रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2026-27 के पहले दो महीने- अप्रैल और मई के नवीनतम उपलब्ध बाजार के नियमित आंकड़े देश की अर्थव्यवस्था की गतिविधियां के इस समय औसत से अधिक होने का संकेत दे रहे हैं और यह रुझान बना रहा तो पहली तिमाही की वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत से अधिक होगी.

गौरतलब है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति (एमएनसी) की इसी सप्ताह हुई समीक्षा बैठक के बाद रिपोर्ट में वर्ष 2026-27 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) वृद्धि के अनुमान को घटा कर 6.6 प्रतिशत कर दिया गया है. अप्रैल में आरबीआई ने 6.9 प्रतिशत का अनुमान लगाया था

इकोरैप में कहा गया है, अप्रैल और मई के उच्च-आवृत्ति वाले संकेतक (मासिक या साप्ताहिक रूप से जारी किये जाने वाले आंकड़े) औसत से अधिक वृद्धि दर दर्शा रहे हैं. यदि यह रुझान जून में भी जारी रहता है, तो हमारा मानना है कि वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही में वृद्धि दर आरबीआई के वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के 6.6 प्रतिशत के अनुमान को पार कर सकती है.

एसबीआई रिसर्च की इस रिपोर्ट में वृद्धि के आधिकारिक अनुमानों और बाजार की आम सहमति के बीच हाल के अप्रत्याशित अंतरों पर सावधानीपूर्वक चर्चा और विश्लेषण की आवश्यकता पर बल दिया गया है.

> रिपोर्ट में कहा गया है, ' अब यह पूरी तरह संभव है कि सरकार की कई नीतिगत पहलों के कारण अनौपचारिक क्षेत्र अ' छा प्रदर्शन कर रहा है. उदाहरण के लिए, लगभग 7.9 करोड़ उद्यम अब एएसयूएसई (असंगठित क्षेत्र की इकाइयों के वार्षिक सर्वे) में पंजीकृत हैं, जो कुल सकल बाजार मूल्य में लगभग 12 प्रतिशत का योगदान करते हैं. एसबीआई रिसर्च का कहना है कि इकाई-स्तरीय आंकड़ों के उसकेअनुमानों से पता चलता है कि औपचारिककरण और डिजिटलीकरण से श्रम उत्पादकता में सुधार होता है.

पीयूष गोयल आज करेंगे भव्य पोर्टल का शुभारंभ

नयी दिल्ली, 07 जून. केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सोमवार को भारत औद्योगिक विकास योजना (भव्य) के पोर्टल का उद्घाटन करेंगे. मंत्रालय ने रविवार को यह जानकारी दी.

मंत्रिमंडल ने देश भर में छोटे-बड़े औद्योगिक पार्क ऑन के विकास की इस योजना के प्रथम चरण में 50 पार्कों के विकास के लिए राज्य सरकारों और निकायों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू करने को अभी हाल में ही मंजूरी दी थी. इसके लिए दिशा निर्देशों को भी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है. इस योजना के तहत केंद्र सरकार इन पार्कों के विकास के लिए प्रति एकड़ एक निश्चित सहायता प्रदान करेगी.

यह योजना केंद्र सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका लक्ष्य देशभर में 100 हाई-टेक 'प्लग-एंड-प्ले' औद्योगिक पार्क विकसित करना है. इस योजना के लिए 33,660 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है. इसका उद्देश्य भारत को एक वैश्विक विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) हब बनाना है.

चावल, चीनी में साप्ताहिक बढ़त, दालों और खाद्य तेलों में घट-बढ़

नयी दिल्ली, 07 जून. घरेलू थोक जिंस बाजारों में बीते सप्ताह चावल का औसत भाव बढ़ गया. चावल के साथ चीनी में भी तेजी देखी गयी जबकि गेहूं के भाव लगभग अपरिवर्तित रहे. खाद्य तेलों और दालों में उतार-चढ़ाव का रुख रहा. सप्ताह के दौरान चावल की औसत कीमत 14 रुपये बढ़कर सप्ताहांत पर 3,851 रुपये प्रति क्विंटल पर पहुंच गयी. गेहूं 2,794 रुपये प्रति क्विंटल पर लगभग स्थिर रहा. आटे का भाव चार रुपये बढ़कर 3,282 रुपये प्रति क्विंटल हो गया. सप्ताह के दौरान चना दाल की औसत कीमत 15 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ गयी. मसूर दाल नौ रुपये और तुअर दाल आठ रुपये महंगी हुई. उड़द दाल नौ रुपये की नरमी रही.

कच्चा तेल 100 डॉलर पार, घरेलू बजट पर दबाव

पश्चिम एशिया संकट से तेल कीमतों में उछाल; पेट्रोल-डीजल महंगे होने की आशंका, महंगाई बढ़ने का खतरा

नई दिल्ली 07 जून. पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई हैं, जिसका सीधा असर भारत सहित कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय माना जा रहा है.

ब्रेंट क्रूड की कीमतों में तेज उछाल के चलते पेट्रोल और डीजल महंगे हो रहे हैं, जिससे घरेलू बजट पर अतिरिक्त बोझ बढ़ने की आशंका है. अर्थशास्त्रियों का कहना है कि यह स्थिति लंबे समय तक बनी रही तो महंगाई दर में और बढ़ोतरी हो सकती है और आम उपभोक्ताओं की जेब पर सीधा असर दिखेगा.

पश्चिम एशिया में तनाव और सप्लाई चेन बाधित होने के कारण कच्चे तेल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी हुई है. ब्रेंट क्रूड जहां पहले 67-68 डॉलर प्रति बैरल के आसपास था, अब 100 डॉलर से ऊपर पहुंच गया है. स्पॉट कीमतें 120 डॉलर प्रति बैरल तक भी देखी जा रही हैं. भारत अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयात करता है, ऐसे में इसका सीधा असर ईंधन कीमतों और परिवहन लागत पर पड़ रहा है

पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें केवल ईंधन तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि इसका असर खाद्य पदार्थों, ट्रांसपोर्ट और उत्पादन लागत पर भी पड़ता है.

> विशेषज्ञों के अनुसार, ईंधन महंगा होने से महंगाई का दबाव बढ़ता है और परिवारों का मासिक बजट प्रभावित होता है. सरकार राहत देने की कोशिश कर रही है, लेकिन वैश्विक बाजार की परिस्थितियों में पूरी तरह नियंत्रण संभव नहीं है. भारत लगातार नवीकरणीय ऊर्जा और वैकल्पिक स्रोतों की ओर बढ़ रहा है ताकि तेल आयात पर निर्भरता कम की जा सके. फिलहाल देश की ऊर्जा जरूरतों का बड़ा हिस्सा आयातित जीवाश्म ईंधन से पूरा होता है, लेकिन सौर और पवन ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में निवेश बढ़ाया जा रहा है. विशेषज्ञों का मानना है कि ऊर्जा विविधीकरण ही दीर्घकाल में तेल कीमतों के झटकों से बचाव का सबसे बेहतर उपाय है.

विदेश यात्रा पर सही कार्ड चुना तो हजारों की बचत

नई दिल्ली 07 जून. विदेश यात्रा की तैयारी करते समय लोग टिकट, वीजा और होटल बुकिंग पर तो खूब ध्यान देते हैं, लेकिन खर्च करने के सही तरीके पर अक्सर कम विचार करते हैं. जबकि विदेश में भुगतान के लिए चुना गया कार्ड आपकी यात्रा का बजट हजारों रुपये तक बढ़ा या घटा सकता है.

क्रेडिट कार्ड, फॉरेक्स कार्ड और प्रीपेड ट्रैवल कार्ड तीनों ही लोकप्रिय विकल्प हैं, लेकिन हर कार्ड की अपनी विशेषताएं और सीमाएं हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि सही कार्ड का चुनाव यात्रा की अवधि, खर्च की आदत और बजट पर निर्भर करता है. इसलिए विदेश जाने से पहले यह समझना जरूरी है कि कौन-सा कार्ड आपके लिए सबसे किफायती और सुविधाजनक रहेगा.

विदेश में भुगतान के दौरान सबसे बड़ी चुनौती करेंसी कन्वर्जन और अतिरिक्त शुल्क होती है. कई यात्री अनजाने में ऐसे कार्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं, जिन पर फॉरेक्स मार्कअप फीस, जीएसटी और अन्य शुल्क लगते हैं. इसका सीधा असर यात्रा के कुल खर्च पर पड़ता है. ऐसे में सही जानकारी आपकी अच्छी-खासी बचत करा सकती है.

फॉरेक्स और प्रीपेड ट्रैवल कार्ड उन यात्रियों के लिए बेहतर विकल्प माने जाते हैं जो अपने खर्च को नियंत्रित रखना चाहते हैं. इन कार्डों में यात्रा से पहले विदेशी मुद्रा लोड कर दी जाती है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि जिस दिन कार्ड में राशि लोड की जाती है, उसी दिन की विनिमय दर लॉक हो जाती है. बाद में डॉलर, यूरो या पाउंड की कीमत बढ़ने पर भी यात्री को अतिरिक्त भुगतान नहीं करना पड़ता.

> सामान्य क्रेडिट कार्ड पर विदेश में खर्च करने पर 2 से 4 प्रतिशत तक फॉरेक्स मार्कअप फीस लग सकती है. ऐसे में दो लाख रुपये के खर्च वाली यात्रा पर चार हजार से आठ हजार रुपये तक अतिरिक्त भुगतान करना पड़ सकता है. फॉरेक्स कार्ड इस अतिरिक्त बोझ से बचाने में मदद करते हैं. क्रेडिट कार्ड होटल बुकिंग, फ्लाइट टिकट, शॉपिंग और आपातकालीन परिस्थितियों में काफी उपयोगी साबित होते हैं. कई कार्ड रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक और ट्रैवल इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं भी देते हैं. हालांकि विदेश में इनके उपयोग पर फॉरेक्स मार्कअप फीस और उस पर लगने वाला जीएसटी खर्च बढ़ा सकता है

पूंजी बाजार से निकाले 37,804 करोड़

मुंबई, 07 जून. विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने जून के पहले सप्ताह में भारतीय पूंजी बाजार से 37,804 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की. शुद्ध निकासी बाजार में लगायी गयी पूंजी और निकाली गयी पूंजी का अंतर है.

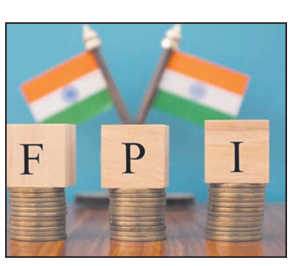

यह लगातार चौथा महीना है जब एफपीआई बिकवाल बने हुए हैं. केंद्रीय डिपॉजिटरी सेवा (सीडीएसएल) से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, इक्विटी, म्यूचुअल फंड और हाइब्रिड उपकरणों में एफपीआई का निवेश कम हुआ है जबकि डेट में उन्होंने शुद्ध रूप से पैसा लगाया है.

सप्ताह के पांच कारोबारी दिन में उन्होंने 42,927 करोड़ रुपये की इक्विटी की शुद्ध बिकवाली की. वहीं, डेट में उन्होंने शुद्ध रूप से 5,326 रुपये लगाये. बीते सप्ताह म्यूचुअल फंड में एफपीआई का निवेश 180 करोड़ रुपये कम हुआ. हाइब्रिड उपकरणों से भी उन्होंने 23.8 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की.

इससे पहले मई में एफपीआई ने भारतीय पूंजी बाजार से 29,919 करोड़ रुपये की शुद्ध निकासी की थी. अप्रैल में उन्होंने 70,786 करोड़ रुपये और मार्च में रिकॉर्ड 1,26,991 करोड़ रुपये निकाले थे.मौजूदा कैलेंडर वर्ष में अबतक एफपीआई ने भारतीय पूंजी बाजार से शुद्ध रूप से 2,56,724 करोड़ रुपये निकाले हैं. अकेले इक्विटी में उसने 2,67,859 करोड़ रुपये की शुद्ध बिकवाली की है.

शेयर बाजारों में बीते सप्ताह में रही गिरावट

मुंबई, 07 जून. घरेलू शेयर बाजारों में बीते सप्ताह रही गिरावट के बाद आने वाले सप्ताह में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के आंकड़ों का असर दिखेगा.जीडीपी के आंकड़े शुक्रवार को बाजार बंद होने के बाद जारी किये गये थे, इसलिए इनका असर सोमवार को बाजार खुलने पर दिखेगा. वित्त वर्ष 2026-27 में जीडीपी की वृद्धि दर 7.7 प्रतिशत रही जबकि चौथी तिमाही में यह 7.8 प्रतिशत दर्ज की गयी. इसके अलावा, निवेशकों की नजर मानसून की प्रगति पर भी रहेगी.

इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन वाहनों में निवेश जारी रहेगा

नई दिल्ली, 7 जून. टाटा मोटर्स के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने कहा है कि कंपनी भविष्य में इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन आधारित कमर्शियल व्हीकल तकनीक में निवेश जारी रखेगी.

उन्होंने कहा कि आने वाले समय में ट्रांसपोर्ट सेक्टर में सिर्फ एक तकनीक पर निर्भर रहना संभव नहीं होगा, बल्कि इलेक्ट्रिक, हाइड्रोजन और साफ-सुथरे आईसी इंजन का संतुलित उपयोग जरूरी होगा.

टाटा मोटर्स ने साफ किया है कि वह क्लीन एनर्जी और नई टेक्नोलॉजी पर अपना फोकस बनाए रखेगी. कंपनी के चेयरमैन एन. चंद्रशेखरन ने स्त्र्ड्ड2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि दुनिया तेजी से क्लीन ट्रांसपोर्ट की ओर बढ़ रही है और इसी के साथ सुरक्षा और तकनीक की मांग भी बढ़ रही है.

समाचार विशेष

टीएमसी में लगी आग से संसद में बदलेगा समीकरण!

कोलकाता. पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) में इस कदर असंतोष उभरा कि पार्टी ही टूट के कगार पर पहुंच गई. टीएमसी में उभरते आंतरिक संकट ने राज्य की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है.

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) इस घटनाक्रम को केवल बंगाल तक सीमित नहीं मान रही. पार्टी के रणनीतिकारों का मानना है कि यदि टीएमसी में विभाजन होता है तो इसका सबसे बड़ा राजनीतिक लाभ संसद में मिल सकता है, जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को कई महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन विधेयकों को पारित कराने के लिए अतिरिक्त समर्थन की आवश्यकता है. इसमें परिसीमन और एक राष्ट्र-एक चुनाव से जुड़े विधेयक अहम हैं. दो तिहाई बहुमत न होने की वजह से संसद के पछिले सत्र में परिसीमन विधेयक सरकार पास नहीं करवा सकी थी.

बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के अनुसार, पश्चिम बंगाल विधानसभा में पार्टी को सत्ता के लिए किसी बाहरी समर्थन की जरूरत नहीं है. असली लक्ष्य संसद में संख्या बल को मजबूत करना है. पार्टी का मानना है कि यदि टीएमसी के भीतर असंतुष्ट गुट अलग होकर नया समूह बनाता है, तो उसके सांसद संसद में एनडीए सरकार का समर्थन कर सकते हैं. इससे केंद्र सरकार के लिए लंबे समय से लंबित महत्वाकांक्षी एजेंडे को आगे बढ़ाना आसान हो जाएगा. बीजेपी नेताओं का कहना है कि टीएमसी के भीतर लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली और नेतृत्व को लेकर चल रहा संघर्ष अंततः पार्टी में औपचारिक विभाजन का रूप ले सकता है.

> **संसद में संख्या बल का खेल**
>
> संसद में संख्या बल बढ़ाने की यह कोशिश इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि केंद्र सरकार को हाल ही में परिसीमन विधेयक के मामले में झटका लगा था. संविधान विधेयक (जिसके तहत लोकसभा सीटों के पुनर्निर्धारण और सदन की अधिकतम सदस्य संख्या 545 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव है) अप्रैल में लोकसभा में आवश्यक दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सका था. बदले राजनीतिक माहौल को देखते हुए केंद्र इस विधेयक को संशोधित रूप में फिर से लाने पर विचार कर रहा है. इसके साथ ही 'वन नेशन, वन इलेक्शन' यानी लोकसभा और विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने से संबंधित विधेयक को भी 2029 के आम चुनावों से पहले आगे बढ़ाने की तैयारी की जा रही है.

सीएम विजय का बड़ा मास्टरस्ट्रोक

कांग्रेस को रास सीट देकर खेल गए बड़ा गेम, 2029 के लोकसभा चुनाव पर नजर

चेन्नई. 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी टीवीके ने राज्य से एकमात्र सीट को सहयोगी दल कांग्रेस को दे दी है. ञ्चक्क्य अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के इस कदम को राजनीतिक हलकों में विपक्षी गठबंधन के भीतर तालमेल और एकजुटता मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम तमिलनाडु में विपक्षी एकता को और मजबूत करेगा तथा टीवीके नेतृत्व वाले गठबंधन की स्थिरता का संदेश देगा.

राज्यसभा चुनाव को तमिलनाडु सरकार के हिसाब से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि टीवीके के नेतृत्व वाले गठबंधन के पास जीत सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त समर्थन मौजूद है. टीवीके विधायकों की संख्या के अलावा, पांच निर्दलीय और सहयोगी विधायकों का समर्थन भी गठबंधन को प्राप्त है, जिन्होंने विधानसभा में विजय के नेतृत्व का समर्थन किया है. इससे राज्यसभा चुनाव के निर्वाचन मंडल में गठबंधन की स्थिति और मजबूत हुई है.

तमिलनाडु में 18 जून को राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए उपचुनाव होगा. इस सीट पर मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके आसानी से अपना उम्मीदवार खड़ा करके जीत सकती थी. संसद के किसी भी सदन में इस नई-नवेली पार्टी का अभी कोई प्रतिनिधित्व भी नहीं है. लेकिन, सीएम विजय ने अपनी पार्टी का उम्मीदवार देने की जगह यह सीट सहयोगी कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ दी है, तो इसके बीचे दूर की सोच है.

> **दो साल के लिए राज्यसभा सीट देकर दिल्ली पर दांव**
>
> तमिनाडु में राज्यसभा की एकमात्र सीट के लिए जो चुनाव हो रहा है, वह एआईएडीएमके के सांसद सीवी शन्मुगम के इस्तीफे की वजह से खाली हुई है. शन्मुगम तमिलनाडु की मैलाम विधानसभा सीट से हालिया चुनाव जीते हैं और इस वजह से उन्हें राज्यसभा सदस्यता छोड़नी पड़ी है. मतलब, कांग्रेस पार्टी के टिकट पर जो उम्मीदवार राज्यसभा जाएगा, उसका कार्यकाल मात्र दो साल का ही रहेगा. मतलब, सीएम विजय ने दो साल के लिए कांग्रेस को राज्यसभा में एक सीट की गारंटी देकर 2029 के लोकसभा चुनावों में सीटों पर तालमेल के लिए अभी से अपना हाथ ऊपर कर लिया है.

अन्नामलाई मौका चूक गए

चेन्नई. पूर्व आईपीएस अधिकारी और तमिलनाडु भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के अन्नामलाई नए सिरे से अपनी राजनीति को संवारने की कोशिश कर रहे हैं. वे दिल्ली में हैं और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से मिल कर पार्टी से विदाई चाहते हैं.

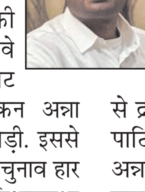

गौरतलब है कि उनको इस बार विधानसभा की टिकट नहीं मिली थी. वे कोयम्बटूर उत्तर की सीट लड़ना चाहते थे लेकिन अन्नाडीएमके ने सीट नहीं छोड़ी. इससे पहले अन्नमलाई दो बार चुनाव हार चुके हैं. वे 2021 का विधानसभा और 2024 का लोकसभा चुनाव लड़े थे लेकिन जीत नहीं पाए थे. अब वे तमिल उप राष्ट्रीयता का मुद्दा लेकर अलग राजनीति करना चाहते हैं. उनको पता है कि भाजपा के साथ यह राजनीति संभव नहीं है. ध्यान रहे उनके साथ युवाओं का समर्थन है और वे अपनी अतरंगी राजनीतिक गतिविधियों से खबरें भी बनाते रहते हैं.

परंतु मुश्किल यह है कि उनके लिए तमिलनाडु में राजनीतिक स्पेस नहीं बन पा रहा है. दूसरी बात यह है कि पिछले 60 साल से द्रविड राजनीति कर रही दोनों पार्टियों डीएमके और अन्नाडीएमके से अलग एक राजनीति शुरू करना चाहते हैं लेकिन इस मामले में भी वे चूक गए. उनसे पहले फिल्म स्टार विजय ने यह राजनीति कर ली.

विशेष | **1 करोड़ से ज्यादा सदस्यों के साथ बिहार की बड़ी पार्टियों में हुई शामिल**

2028 मिशन की ओर जदयू का बड़ा कदम

पटना. बिहार की जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने अपने संगठन विस्तार अभियान के तहत एक करोड़ से अधिक सदस्य बनाने का दावा करते हुए सोशल मीडिया पर एक पोस्ट सांझा किया है. पार्टी ने लिखा कि उसने सदस्यता के मामले में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है. एक करोड़ से अधिक सदस्य बनाने के बाद जदयू अब बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टियों में शामिल हो गई.

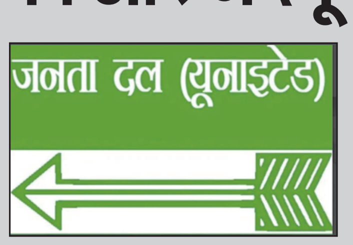

पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में दावा किया है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू किए गए सदस्यता अभियान के तहत 2 जून 2026 तक कुल 1,00,01,925 सदस्य बनाए जा चुके हैं. सदस्यता अभियान की शुरूआत 6 दिसंबर 2025 को हुई थी. 1 करोड़ से अधिक सदस्यों के साथ जद (यू) परिवार ने संगठनात्मक मजबूती का नया इतिहास रचा है. यह उपलब्धि बिहार की जनता के विश्वास, कार्यकर्ताओं की मेहनत और माननीय नीतीश कुमार जी के दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है. संजय झा ने बूथ स्तर तक अभियान को सफल बनाने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी और बिहार की जनता को भी समर्थन देने के लिए धन्यवाद दिया. उन्होंने कहा कि जेडीयू नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहारवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने और राज्य की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है.

2028 तक सबसे मजबूत बनने का लक्ष्य- संजय झा ने बताया कि पार्टी का यह सदस्यता अभियान 2025 से 2028 तक चलने वाली व्यापक संगठनात्मक योजना का हिस्सा है. छह महीने के भीतर एक करोड़ से अधिक सदस्य जोड़ना 2028 तक राज्य की सबसे मजबूत राजनीतिक ताकत बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. बता दें कि हाल के वर्षों में जेडीयू के चुनावी प्रदर्शन में भी सुधार देखने को मिला है. वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 43 सीटें जीती थीं, के लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने 12 सीटें हासिल कीं, जो भाजपा के बराबर थीं. 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने बेहतर चुनावी प्रदर्शन के साथ 85 सीटों पर जीत दर्ज की थी.

> **संजय झा के प्रयासों का परिणाम**
>
> बता दें कि जेडीयू के पार्टी नेताओं का मानना है कि संगठन के विस्तार में तेजी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के प्रयासों का भी सफल परिणाम है. सदस्यता के आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो बिहार की प्रमुख पार्टियों के बीच अब प्रतिस्पर्धा और भी तेज हो गई क्योंकि भाजपा के लगभग 1.56 करोड़ सदस्य हैं, जबकि राजद भी एक करोड़ से अधिक सदस्यों का दावा कर चुकी है. तो वहीं जेडीयू के मुताबिक पार्टी अब एक करोड़ सदस्यता का आंकड़ा पार करने के साथ वह राज्य के सबसे बड़े राजनीतिक संगठनों की श्रेणी में शामिल हो गई है. इस उपलब्धि को जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने पार्टी के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि नीतीश कुमार के नेतृत्व में जनता के बढ़ते विश्वास को दिखाती है और विकसित बिहार के संकल्प के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है. जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 21 जून को आयोजित होगी, जिसमें संगठनात्मक मुद्दों और भविष्य की रणनीतियों पर चर्चा की जा सकती है.